



16 मिनट	8	10	5 + 1	GS1 • 1 GS2 • 8 GS3 • 9
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट पदों के लिए जजों की सिफारिश की

क्यों जरूरी: न्यायिक नियुक्तियाँ और कॉलेजियम सिस्टम: न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण GS2 विषय।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

2 भारत ने चेतावनी दी कि वीटो पावर के बिना UNSC सुधार से सेकंड-क्लास स्टेटस पैदा होगा

क्यों जरूरी: UNSC में सुधार और वीटो पावर (Veto Power): बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन (Global Governance) से संबंधित GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

3 मंत्रालय ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 ईंधन की अनुमति देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया

क्यों जरूरी: इथेनॉल ब्लेंडिंग और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन: ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonization) पर एक GS3 केस स्टडी।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

4 ओपनएआई मॉडल्स ने हार्मोनिक एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में बड़ी सफलता हासिल की

क्यों जरूरी: AI-आधारित वैज्ञानिक खोज: यह अनुभवजन्य अनुसंधान (Empirical Research) और सैद्धांतिक भौतिकी (Theoretical Physics) के विकास से संबंधित GS3 का एक महत्वपूर्ण विषय है।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

5 आर्बना चक्रवाती तूफान के करीब आने पर IMD ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया

क्यों जरूरी: आपदा प्रबंधन और बहु-एजेंसी समन्वय: तटीय लचीलेपन (Coastal Resilience) पर GS3 केस स्टडी।

GS3 • पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

P

आज का आँकड़ा

E20

भारत ने 2025 में अपना E20 फ्यूल ब्लेंड लक्ष्य हासिल कर लिया।

स्टैटिक से जोड़ें

Central Motor Vehicles Rules, 1989

सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (Central Motor Vehicles Rules), 1989: फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 के साथ E100 को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। खबर में: मंत्रालय ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 ईंधन की अनुमति देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया।

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट पदों के लिए जजों की सिफारिश की

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर को एक प्रस्ताव जारी किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के पदों के लिए चार न्यायाधीशों और बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए दो न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है।

याद रखें

- कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) — सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मैकेनिज्म।
- जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती — तेलंगाना के लिए अनुशंसित।
- जस्टिस सुधीर सिंह — उत्तराखंड के लिए अनुशंसित।

मेन्स कोण न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में कॉलेजियम प्रणाली के महत्व और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसकी भूमिका की सूक्ष्मताओं पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142679

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

भारत ने चेतावनी दी कि वीटो पावर के बिना UNSC सुधार से सेकंड-क्लास स्टेटस पैदा होगा

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, एंबेसडर हरीश परवथनेनी ने चेतावनी दी है कि UNSC में वीटो पावर के बिना स्थायी सदस्यता देने से उन सदस्यों की स्थिति 'सेकंड-क्लास' (second-class) जैसी हो जाएगी।

याद रखें

- वीटो पावर (Veto Power) — भारत का तर्क है कि इस पावर के बिना स्थायी सीटें 'सेकंड-क्लास' स्टेटस (second-class status) पैदा करती हैं।
- भारत के UNSC लक्ष्य — एक स्थायी सीट और 2028-29 कार्यकाल के लिए एक गैर-स्थायी सीट की मांग।
- जून 2027 कॉन्टेस्ट — भारत, नॉन-परमानेंट सीट के लिए ताजिकिस्तान के खिलाफ दावेदारी पेश कर रहा है।

मेन्स कोण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और वैश्विक भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में वीटो शक्ति के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142673

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

मंत्रालय ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 ईंधन की अनुमति देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया

चर्चा में क्यों: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के होमोलोगेशन (homologation) को आसान बनाने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन किया है, ताकि इन वाहनों में E100 (100% एथेनॉल) ईंधन के उपयोग की अनुमति दी जा सके।

याद रखें

- सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (Central Motor Vehicles Rules), 1989: फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 के साथ E100 को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया।
- E100 में 100% एथेनॉल होता है, जबकि E85 में 85% तक एथेनॉल होता है।
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI): तकनीकी, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत एजेंसी।

मेन्स कोण फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों और E100 ईंधन को बढ़ावा देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) के लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142666

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

ओपनएआई मॉडल्स ने हार्मोनिक एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में बड़ी सफलता हासिल की

चर्चा में क्यों: OpenAI ने घोषणा की है कि उसके AI मॉडल्स ने 'लोकल स्मूथिंग कन्जेक्चर' (local smoothing conjecture) को सिद्ध करके और 'एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथिसिस' (Exponential Time Hypothesis) को गलत साबित करके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

याद रखें

- लोकल स्मूथिंग कन्जेक्चर (Local smoothing conjecture) — OpenAI मॉडल्स द्वारा हर स्पेसियल डायमेंशन (spatial dimension) में सिद्ध किया गया।
- एक्सपोनेंशियल टाइम हाइपोथिसिस (Exponential Time Hypothesis) — OpenAI मॉडल्स द्वारा गलत साबित किया गया।
- क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (Quantum chromodynamics) — OpenAI मॉडल्स ने इसके अस्तित्व का प्रमाण प्रदान किया।

मेन्स कोण वैज्ञानिक खोजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण से अनुभवजन्य अनुसंधान (empirical research) की पारंपरिक कार्यप्रणाली और उच्च-स्तरीय सैद्धांतिक भौतिकी के लोकतंत्रीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142646

आर्बना चक्रवाती तूफान के करीब आने पर IMD ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया

चर्चा में क्यों: आगामी चक्रवाती तूफान 'Arnab' के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया और लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिल सके।

याद रखें

- NDRF — National Disaster Response Force भारत में आपदा प्रतिक्रिया (disaster response) के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- आंध्र प्रदेश — भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म Arnab से प्रभावित हुआ।
- 54 रिलीफ कैम्प (Relief camps) — 31,405 लोगों को आवास देने के लिए स्थापित किए गए।

मेन्स कोण तटीय भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे और चक्रवातीय जोखिमों को कम करने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142665

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कर्नाटक की मतदाता सूची से 99.32 लाख नाम हटाए

चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के बाद अंतिम मतदाता सूची (electoral roll) प्रकाशित की है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची से 99.32 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं।

याद रखें

- चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (Chief Electoral Officer) — वह अथॉरिटी जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) — एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक में 99.32 लाख नाम हटा दिए गए।
- 16.39 लाख — सूची से हटाए गए मृत मतदाताओं की संख्या।

मेन्स कोण भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142710

ECI ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में अतिरिक्त घोषणा फॉर्म का बचाव किया

चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने प्रिया मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान हटाए गए मतदाताओं के लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र के उपयोग का बचाव किया।

याद रखें

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — मतदाता सूची प्रबंधन के लिए Form 6 के साथ अतिरिक्त डिक्लरेशन फॉर्म (declaration forms) का उपयोग करता है।
- ज्ञानेश कुमार — भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।
- Statutory amendment — ECI ने तर्क दिया कि अतिरिक्त घोषणा फॉर्म (declaration form) एक statutory amendment नहीं है।

मेन्स कोण मतदाता सूची प्रबंधन के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश तैयार करने में भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142715

प्रेस की आजादी पर खतरा, DNPA ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

चर्चा में क्यों: डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और इसके 2025 के नियमों पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

याद रखें

- DNPA: 21 पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association)।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025।

मेन्स कोण डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों और प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/142703

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा: तमिलनाडु ने नॉन-हाई राइज बिल्डिंग (non-high rise building) की ऊंचाई की सीमा को 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दिया है।

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

IIT काउंसलिंग: RTI डेटा से पता चलता है कि अधिकांश IITs, UGC के एक काउंसलर प्रति 500 छात्र के अनुपात और फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन (faculty representation) के नियमों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

ECI हलफनामा: CEC और कमिश्नरों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह हटाने की प्रक्रिया (removal process) की मांग करते हुए 250 पत्रों का एफिडेविट (affidavit) दायर किया।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद: लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अन्य शहरों के 11 निर्वाचन क्षेत्रों (constituencies) के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है।

मानचित्र

चर्चा में स्थान

आंध्र प्रदेश

भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म Arnab से प्रभावित हुआ।

जोजरी-लूणी-बांदी नदी तंत्र

राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों का स्थल।

बेलगावी

वह स्थान जहाँ गन्ना किसानों और शुगर मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता (mediation) हुई।

अवैध खनन: सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में अवैध खनन की CBI जांच के संबंध में राजस्थान को चेतावनी दी।

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

गन्ने की कीमतें: कर्नाटक के CM ने किसानों की कीमतों को केंद्र सरकार की न्यूनतम बिक्री मूल्य (minimum selling price) से जोड़ने के गतिरोध को सुलझाया।

बुलेट ट्रेन: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 2027 में उद्घाटन की योजना है।

आत्मनिर्भरता 2.0: डिफेंस मिनिस्टर ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाय चैन के जरिए आयात पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।

FCNR(B) स्कीम: RBI और सरकार ने \$130 बिलियन से अधिक जुटाए, जबकि अनुमानित पुनर्भुगतान (repayment) \$160 बिलियन से \$170 बिलियन है।

FPI इक्विटी बिक्री: 2026 में AI-driven मार्केट कंसंट्रेशन रिस्क के बीच FPIs ने भारतीय इक्विटीज में ₹4.55 लाख करोड़ की नेट सेल की।

1 जस्टिस मनश रंजन पाठक को किस हाई कोर्ट के लिए रिक्त किया गया था?

- (a) मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (b) गुजरात हाई कोर्ट
(c) महाराष्ट्र हाई कोर्ट (d) केरल हाई कोर्ट

2 भारत जून 2027 में गैर-स्थायी सीट (non-permanent seat) के लिए किस देश के खिलाफ विरोध कर रहा है?

- (a) किर्गिज़स्तान (b) उज़बेकिस्तान
(c) ताजिकिस्तान (d) तुर्कमेनिस्तान

3 भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (flex-fuel vehicles) और एथेनॉल ब्लेंडिंग (ethanol blending) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ARAI वाहन होमोलोगेशन (homologation) और टाइप अप्रूवल (type approval) को सत्यापित करने के लिए अधिकृत एजेंसी है।
2. सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (Central Motor Vehicles Rules), 1989 में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 फ्यूल की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया।
3. E100 फ्यूल में 85% तक इथेनॉल (ethanol) की मात्रा होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

4 AI-driven वैज्ञानिक खोजों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. OpenAI मॉडल्स ने क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (quantum chromodynamics) के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान किया।
2. OpenAI मॉडल्स ने Exponential Time Hypothesis को सिद्ध किया।
3. OpenAI मॉडल्स ने हर स्पेसियल डायमेंशन (spatial dimension) में लोकल स्मूथिंग कंजेक्चर (local smoothing conjecture) को सिद्ध किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5 भारत में आपदा प्रतिक्रिया (disaster response) के लिए मुख्य संस्था के रूप में किस एजेंसी की पहचान की गई है?

- (a) SCDF (b) इंसास
(c) NDRF (d) NIDM

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में कॉलेजियम प्रणाली के महत्व और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसकी भूमिका की सूक्ष्मताओं पर चर्चा कीजिए।

(०) ५ (१) ४ (२) ३ (३) २ (४) १ • २०२६



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।